



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2000/6 वीष, 1922

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 दिसम्बर, 2000

संख्या 1-79/2000-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का

विधेयक संख्यांक १२) जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनाएं राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय मण्डारी,  
सचिव।

2000 का विशेषक संख्यांक 22

## हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2000 है ।

1954 का 6

2. 'हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 में, उप-धारा (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 7 का संशोधन ।

“(1) राजस्व अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) वित्तायुक्त ;
- (ख) आयुक्त ;
- (ग) अपर आयुक्त ;
- (घ) उपायुक्त ;
- (ङ) बन्दोबस्त अधिकारी ;
- (च) अपर उपायुक्त ;
- (छ) उप-मण्डल अधिकारी (मिविल) ;
- (ज) सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ;
- (झ) सहायक आयुक्त ;
- (ञ) कलक्टर ;
- (ट) प्रथम ग्रेड का सहायक कलक्टर ; और
- (ठ) द्वितीय ग्रेड का सहायक कलक्टर ;

3. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

धारा 33 का संशोधन ।

(क) उप-धारा (5) और (6) में “बन्दोबस्त कलक्टर” शब्दों के लिए शब्द “बन्दोबस्त अधिकारी” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (7) में, परन्तु में, “अंतिमतः विनिश्चित” शब्दों के लिए शब्द “विनिश्चित” प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. मूल अधिनियम की धारा 35 में, उप-धारा (7) में “सभी पक्षकारों के” शब्दों के स्थान पर “उपस्थित सभी पक्षकारों के” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

धारा 37 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 37 में, उप-धारा (3) में “मूल वाद के रूप में” शब्दों के पश्चात् “किन्तु इसके अन्तर्गत हक के प्रश्न से सम्बन्धित मामले नहीं होंगे” जोड़े जाएंगे।

धारा 46 का संशोधन। 6. मूल अधिनियम की धारा 46 में, “उसके विनिश्चय हेतु” शब्दों के पश्चात् “किन्तु इसके अन्तर्गत हक के प्रश्न से सम्बन्धित मामले नहीं होंगे” शब्द जोड़े जाएंगे।

धारा 51 का संशोधन। 7. मूल अधिनियम की धारा 51 में, “पांच गुणा” शब्दों के स्थान पर “दो गुणा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 163 का संशोधन। 8. मूल अधिनियम की धारा 163 में,—

(क) उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “दो हजार” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-धारा (2) में “दस हजार” शब्दों के स्थान पर “पांच हजार” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) में, भू-विधियों पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, हाल ही में संशोधन किया गया था। राज्य में बार काउंसिल एवं बार असोशिएशनों ने अधिनियम में किए गए कतिपय संशोधनों पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। बार असोशिएशनों की संयुक्त कार्यवाही समिति, भारतीय किसान संघ, किसान मजदूर और राजस्व अधिकारी असोशिएशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई तारीख 28-9-2000 को बैठक में उठाए गए सभी वाद विषयों पर ब्यौर-वार विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार ने, अधिनियम के उपबन्धों को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव स्वीकार किए : -

1. धारा 7 का संशोधन.—धारा 9 के अनुरूपता धारा 7 में सभी राजस्व अधिकारी जोड़े जाएंगे।
2. धारा 33 का संशोधन.— (क) शब्द “बन्दोबस्त कलक्टर” शब्दों के स्थान पर “बन्दोबस्त अधिकारी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।  
(ख) “अन्तिमतः विनिश्चित” शब्दों के स्थान पर “विनिश्चित” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. धारा 35 का संशोधन.—इन्तकालों के सत्यापन में देरी में बचने के लिए “सभी पक्षकारों के” शब्दों के स्थान पर “उपस्थित सभी पक्षकारों के” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. धाराओं 37 और 46 का संशोधन.—उपबन्धों को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से, धारा 37 और 46 के अन्त में “किन्तु इसके अन्तर्गत हक के प्रश्न से सम्बन्धित मामले नहीं होंगे” शब्द जोड़े जाएंगे।
5. धारा 51 का संशोधन.—भू-राजस्व केवल संकेतात्मक और न्यूनतम होना चाहिए।
6. धारा 163 का संशोधन.—अधिकांताओं पर अधिरोपित की जाने वाली जुर्माने की शास्ति घटाकर पांच हजार रुपए से दो हजार रुपए और दस हजार से पांच हजार की जाए।

इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

राजन सुशान्त,  
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख ..... , 2000.

---

**बितीय ज्ञापन**

-शून्य-

---

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन**

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (SECOND AMENDMENT) BILL, 2000

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-first Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Second Amendment) Act, 2000.

Short title.

6 of 1954

2. In section 7 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter called the "principal Act"), for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

Amendment of section 7.

"(1) There shall be the following classes of Revenue Officers, namely :—

- (a) the Financial Commissioner;
- (b) the Commissioner;
- (c) the Additional Commissioner;
- (d) the Deputy Commissioner;
- (e) the Settlement Officer;
- (f) the Additional Deputy Commissioner;
- (g) the Sub-Divisional Officer (Civil);
- (h) the Assistant Settlement Officer;
- (i) the Assistant Commissioner;
- (j) the Collector;
- (k) the Assistant Collector of first grade; and
- (l) the Assistant Collector of second grade."

3. In section 33 of the principal Act,—

Amendment of section 33.

- (a) in sub-sections (5) and (6), for the words "Settlement Collector", the words "Settlement Officer" shall be substituted; and
- (b) in sub-section (7), in proviso, for the words "finally decided", the word "decided" shall be substituted.

4. In section 35 of the principal Act, in sub-section (7), for the words "all the parties", the words "all the parties present" shall be substituted.

Amendment of section 35.

5. In section 37 of the principal Act, in sub-section (3), after the words "an original suit", the words "but shall not include the matters pertaining to the question of title" shall be added.

Amendment of section 37.

Amend-  
ment of  
section 46.

6. In section 46 of the principal Act, after the words "to decide the same", the words "but shall not include the matters pertaining to the question of title" shall be added.

Amend-  
ment of  
section 51.

7. In section 51 of the principal Act, for the words "exceed five times", the words "exceed two times" shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 163.

8. In section 163 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), in clause (c), for the figure and sign "5,000/-", the figure and sign "2,000/-" shall be substituted; and
- (b) in sub-section (2), for the words "ten thousand", the words "five thousand" shall be substituted.



## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) was amended recently on the basis of the recommendations of the High Powered Committee on Land Laws. The Bar Council and Bar Associations of the State have shown their resentment to certain amendments carried out in the Act.

In the meeting held on 28-9-2000 with the representatives of Bar Association's Joint Action Committee, Bhartiya Kisan Sangh, Kisan Morcha and Revenue Officers Association, after detailed discussion on all the issues raised in the meeting, the State Government accepted following suggestions in order to make the provisions of the Act *ibid* more clear :—

1. *Amendment of section 7.*—All the Revenue Officers be added in section 7 in conformity with section 9.
2. *Amendment of section 33.*—(a) The words “Settlement Officer” to be substituted for the words “Settlement Collector”.  
(b) The words “finally decided” be substituted by the word “decided”.
3. *Amendment of section 35.*—In order to avoid delay in attestation of mutations the words “all the parties” be substituted by the words “all the parties present”.
4. *Amendment of sections 37 and 46.*—In order to make the provisions more clear, at the end of the sections 37 and 46, the words “but shall not include the matters pertaining to question of title”, be added.
5. *Amendment of section 51.*—The land revenue should be only symbolic and minimum.
6. *Amendment of section 163.*—The penalty of fine to be imposed on the encroachers be reduced from Rs. 5,000/- to Rs. 2,000/- and from Rs. 10,000/- to Rs. 5,000/-.

This has necessitated the amendments in the Act *ibid*.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

RAJAN SUSHANT,  
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

Dated the ..... 2000.

---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

•Nil.

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Nil